जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

चूरू

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

फोनः- 256906, 256907, फैक्सः- 01562-256908 वर्षः 13 संख्याः 275 प्रभात चूरू, बुधवार 2 फरवरी, 2022 पो. रजि. न. चूरू/084/2019-21 पृष्ठ 8 मूल्य 2.00 रु.

सरिस्का से बाघ एस.टी.-13 गायब

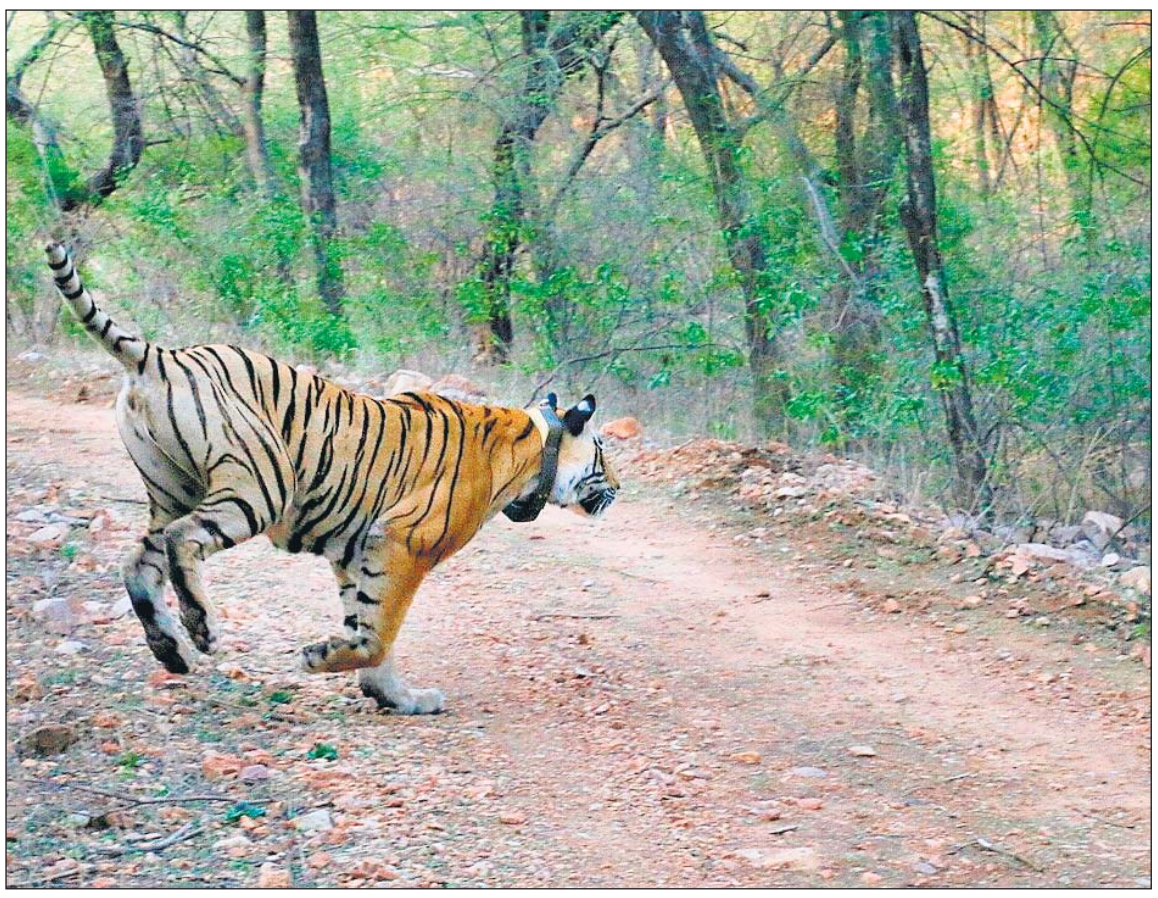

सरिस्का से टाइगर एस.टी. 13 गायब हो गया है, पिछले 13 दिनों से सरिस्का प्रशासन को एस.टी.-13 एक बार भी कहीं नज़र नहीं आया है, और ना ही इसका कोई पगमार्क मिला है। इस मामले में सरिस्का प्रशासन सवालों के घेरे में है। यहां जंगल से लगते एरिया में करीब 7 दिन पहले 3 तेंदुओं का शिकार हो गया था। यह मामला सुलझा भी नहीं कि अब टाइगर एसटी-13 के गायब होने से प्रशासन की चिंता और बढ़ गई है। जंगल में लगे कैमरों में भी टाइगर की कोई फोटो नहीं दिखाई दी है। इस कारण सरिस्का प्रशासन के हाथ पैर फूले हुए हैं। यह भी डर है कि, कहीं टाइगर शिकारियों का निशाना तो नहीं बन गया। हालांकि वन विभाग के अधिकारी बराबर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। टाइगर एसटी-13 का रेडियो कॉलर भी काम नहीं कर रहा है। जिसके कारण प्रशासन की चिंता और ज्यादा गहरा गई हैं। सरिस्का प्रशासन के अधिकारियों का कहना है कि, पहले भी टाइगर एसटी-13 के कई दिन तक पगमार्क नहीं मिले थे। लेकिन कई दिन बाद टाइगर की साइटिंग हो गई थी। कई बार टाइगर टैरिटरी के अलावा जंगल में दूसरी तरफ चला जाता है। लेकिन इस बार टाइगर के कोई पता नहीं चल रहा है।

वित्त मंत्री ने ''गैर राजनीतिक'' बजट पेश किया इस बार

पांच महत्वपूर्ण विधानसभा चुनावों की छाया में प्रस्तुत बजट में लोग, सस्ती लोकप्रियता से ओत-प्रोत, रियायतों व छूटों की भरमार वाला बजट होने की उम्मीद कर रहे थे

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 1 फरवरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक शक्तिशाली और मर्दाना बजट पेश किया है जिसमें काफी उत्साह अन्तर्निहित है। उन्होंने महत्वाकांक्षी दिखाई है और अगले 25 वर्षों के लिए देश में ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश की है जो सर्वसाधारण के लिए एक ''अमृत काल'' होगा।

विधानसभा चुनावों के बीच, बढ़ते वित्तीय घाटे और लोकलुभावन उपायों के दबावों की परवाह ना करते हुए वित्त मंत्री ने इन्फ्रास्ट्रक्चर में व्यय और निवेश में गति लाने वाली एक समग्र आर्थिक रणनीति अपनाई है।

बजट अनुमानों में 6.8 प्रतिशत का संशोधित वित्तीय घाटा जी.डी.पी. का 6.9 प्रतिशत अनुमानित है। वर्ष 2022-23 में वित्तीय घाटा जी.डी.पी. का 6.4 प्रतिशत अनुमानित है, जो कि वित्तीय समेकन के वृहद परिप्रेक्ष्य के अनुरूप है।

एयरपोर्ट्स, रेल्वेज़, माल ट्रांज़िट, इन्टर मोडल ट्रांसपोर्ट हब्स सहित ऐसे सात इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र हैं, जिन पर गहन जोर दिया गया है।

एक तरह से यह नैशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर कार्यक्रमों के लिए एक बड़ी बजट स्टोरी है। सीतारमण अर्थव्यवस्था को हौंसला और संसाधन प्रदान करने की कोशिश कर रही हैं, ताकि वह कथित ''गति शक्ति'' कार्यक्रम के अनुरूप दौड़ सके। उन्हें उम्मीद है कि यह बड़े निवेश अर्थव्यवस्था को पर्याप्त गतिशीलता प्रदान करेंगे और रोजगार व आय को कई गुना सृजित करेंगे।

उनका मानना है कि, इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण में बड़े पैमाने के निवेश से आर्थिक वृद्धि और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। परिणामस्वरूप, यह ऐसा बजट नहीं है प्रशंसा की वर्षा जाए।

वित्त मंत्री यह दावा कर रही हैं कि, 14 सैक्टर्स के लिए लायी गई पी.एल.आई. स्कीम्स ही 60 लाख नौकरियां सृजित करेंगी, 30 लाख करोड़ का आर्थिक लाभ देंगी।

गरीब और मध्यम वर्ग की अनदेखी को लेकर सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने बजट की आलोचना की है। पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम ने इसे ''सर्वाधिक पूंजीवादी'' मानते हुए इसकी आलोचना की है। तृणमूल कांग्रेस इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकती थी कि, यह बजट गरीब-विरोधी है।

कहा जा सकता है कि वैश्विक महामारी के बाद का यह एक ऐसा बजट है जिसने महामारी के सर्वाधिक पीड़ितों की क्रय शक्ति पर ध्यान नहीं दिया है। इस प्रक्रिया में उन्होंने एक ऐसा बजट दिया है, जो राजनीतिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। बजट निर्माण में वित्त मंत्री के पास ये विकल्प थे कि वे या तो भावुकता जारी रखते हुए आर्थिक सौगात देकर लोकलुभावन मार्ग का अनुसरण करतीं या कोई मूलभूत दिशा निर्देश देकर कोई

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- पर, वित्त मंत्री ने सस्ती लोकप्रियता का रास्ता (पॉप्युलिस्ट रूट) का चयन न कर, इन्फ्रास्ट्रक्चर के बड़े-बड़े प्रोजैक्ट में पूंजी लगाने का विकल्प अपनाया।
- वित्त मंत्री ने अपने भाषण में भी कहा, यह आशा है कि, इन्फ्रास्ट्रक्चर में भारी सरकारी ''इन्वैस्टमैंट'' से 60 लाख नौकरियां उपलब्ध होंगी तथा 30 लाख करोड़ का इकोनॉमिक उत्पादन व आऊटपुट जनरेट करेगा।
- यह सच है कि, इस बजट को भूरि-भूरि प्रशंसा मिलने वाली नहीं है, बल्कि कुछ राजनीतिज्ञों ने तो इसे अब तक का सबसे ज्यादा पूंजीवादी बजट भी कहा है।
- वित्त मंत्री ने बड़े पूंजी निवेश पर ध्यान साधते हुए, टैक्स व एक्साइज़ ड्यूटी आदि से कोई छेड़छाड़ नहीं की, उन्हें अछूता ही छोड़ दिया है।

वित्त मंत्री सीतारमण ने रेल बजट में भी भारी ''इन्फ्रास्ट्रक्चर'' खर्च का विकल्प लिया

रेल उपकरण, जैसे वैगन आदि के निर्माता, लाइन बिछाने वाली बड़ी कम्पनियां, जैसे एल्स्टॉम व हिटाची आदि बहुत प्रसन्न हैं

-श्रीनन्द झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 1 फरवरी। भारतीय रेल एल्यूमिनियम बॉडी वाली 400 वन्दे भारत रेल गाड़ियों (160 किमी सैमी हाई स्पीड) का निर्माण करेगी, जबकि अगले तीन वर्षों में 100 ग्रीनफील्ड मल्टीमोडल कार्गो टर्मिनलों का भी निर्माण होगा।

आज संसद में अपने बजट भाषण को पढ़कर प्रस्तुत करते हुये, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह घोषणा भी की कि, 2022-23 के दौरान ट्रेन कोलिज़न अवॉयडैंस सिस्टम (टी-सी.ए.एस.) के अन्तर्गत, 2000 किमी ट्रैक का काम पूरा कर लिया जायेगा। बजट प्रस्तावों में, देश में मास रैपिड ट्रान्ज़िट सिस्टम तथा मैट्रो प्रोजेक्ट विकसित करने के लिये 23875 करोड़ रु. खर्च करने का प्रावधान किया गया है।

- पर, रेल के फाइनैंस समझने वाले विशेषज्ञ की यह भी राय है कि यह भारी इन्वैस्टमैंट भारतीय रेल, बैंकों, फाइनैन्शियल कम्पनियों व सरकार से ऋण लेकर कर रही है तथा अभी ऋण अदायगी व ब्याज के भुगतान पर ''मोरेटोरियम'' लगा है, पर जब मोरेटोरियम का समय समाप्त होगा तो एक साथ भारतीय रेल पर भारी आर्थिक बोझ आयेगा और क्या भारतीय रेल इस संकट को भूल पायेगा।

रेल गाड़ियों तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के लिये 2.25 करोड़ रु. के पूंजीगत व्यय तथा इण्डियन रेलवे की और अधिक प्रतिबद्धता के चलते इस उद्योग के सर्वोच्च अधिकारी काफी उत्साहित एवं प्रसन्न हैं।

एल्स्टॉम इंडिया के प्रबंध निदेशक एलेन स्पोर ने कहा, ''यह एक प्रगतिशील एवं ग्रोथ केन्द्रित बजट है, जो अर्थव्यवस्था पर बहुत आधक सकारात्मक असर डालने वाला तथा प्रोजेक्टों के तेज क्रियान्वयन को प्रोत्साहित करने वाला सिद्ध होगा। मैट्रो डिज़ाइन सिस्टम को स्तरीय बनाने के लक्ष्य से बनाई जाने वाली नीतियाँ, निर्माताओं को अत्यावश्यक स्थिरता प्रदान करेंगी।

नॉर ब्रैमसी (इंडिया) के प्रबन्ध निदेशक दीपांकर घोष ने कहा है, ''रेल -क्षेत्र के लिये की गईं ये पहल कायापलट करने वाली हैं क्योंकि ये ग्रोथ के भविष्य का खाका प्रस्तुत कर रही हैं।'' टैल्गो इंडिया के प्रबन्ध निदेशक सुब्रत नाथ ने कहा, ''रेल गाड़ियों तथा यात्रियों के लिहाज से, बजट-प्रस्ताव सकारात्मक हैं।'' हिटाची इंडिया के निदेशक मंगल देव ने कहा, ''रेल -क्षेत्र के लिये वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणाएं स्थाई इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में मदद करेंगी। प्राइवेट तथा सरकारी क्षेत्रों को इन प्रोजेक्टों में, जोखिम तथा लाभ में आनुपातिक रुप से भागीदारी एवं साझेदारी करने की जरुरत है।''

सीतारमण ने पूर्व घोषित बड़े प्रोजेक्टों, जैसे- इण्डियन रेलवे (आई. आर.) की पुनर्निमाण योनजाओं, रेलवे उत्पादन इकाइयों को कॉर्पोरेशनों का रुप

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

''क्रिप्टो करैन्सी''

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 1 फरवरी। पूर्व केन्द्रीय मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता, पी. चिदंबरम ने मंगलवार को जोर देते हुए कहा कि, वित्त मंत्री ने आज से क्रिप्टो करैन्सी को एक तरह से वैध करने की घोषणा कर दी है।

उन्होंने कहा कि, वित्त मंत्री ने देश

- चिदंबरम के अनुसार एक प्रकार से वित्त मंत्री सीतारमण ने क्रिप्टो करैन्सी को ''लीगल'' करार दे दिया है। पर भारत की 99.9 प्रतिशत जनता ''डिजिटल एसैट'' का मतलब तक नहीं समझती।

के काफी अमीर लोगों के इशारे पर ''डिजिटल असैट'' शब्द का आविष्कार किया है। यह भली-भांति जानते हुए कि, यह शब्द क्रिप्टो करैन्सी के अतिरिक्त कुछ नहीं है। उन्होंने ध्यान दिलाया कि, वित्त मंत्री की घोषणानुसार रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (आर.बी.आई.) इसे जारी करेगा और डिजिटल असैट्स के ट्रांसफर पर एक विशेष दर पर टैक्स

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'आरोप लग रहा है तो जांच होनी चाहिए, जांच सी.बी.आई. करे या कोई दूसरी एजेंसी'

रीट मामले में राजीव गांधी स्टडी सर्कल पर लगे आरोपों पर बोले सचिन पायलट

जयपुर, 1 फरवरी (का.प्र.)। रीट परीक्षा पेपर लीक को लेकर राजीव गांधी स्टडी सर्किल पर लग रहे आरोपों को लेकर पूछे गए सवाल पर राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि, अगर कोई ऐसा आरोप लग रहा है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। चाहे यह जांच सीबीआई करे या कोई दूसरी एजेंसी, लेकिन समयबद्ध तरीके से पूरी हो और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो।

दरअसल रीट परीक्षा मामले में गिरफ्तार प्रदीप पाराशर जो कि स्टेट कोऑर्डिनेटर था वह राजीव गांधी स्टडी सर्किल से जुड़ा है। वही माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के बर्खास्त अध्यक्ष डीपी जारोली भी राजीव गांधी स्टडी सर्किल से जुड़े हुए हैं।

इसके राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर राज्य के मंत्री सुभाष गर्ग हैं और चेयरपर्सन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। ऐसे में सचिन पायलट का यह बयान कि यदि

- ''इस मामले में जो भी दोषी पाया जाए, चाहे वह कितने भी बड़े पद पर क्यों ना हो, कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी ही चाहिए।''

राजीव गांधी स्टडी सर्किल को लेकर आरोप लग रहे हैं और इनकी जांच पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए। राजस्थान की राजनीति में महत्वपूर्ण बयान बन सकता है।

इस मामले में मीडिया से बात करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि, रीट भर्ती मामले में पद बढ़ाने के लिए मैंने खुद मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। यह बेरोजगार और युवाओं से जुड़ा हुआ गंभीर मुद्दा है, क्योंकि रीट परीक्षा मध्यम और ग्रामीण परिवेश के लोग देते हैं। 26 लाख युवाओं के साथ ही इस परीक्षा से जुड़े करीब सवा करोड़ परिवार भी प्रभावित हो रहे हैं। इसी के साथ पायलट ने कहा कि गड़बड़ी सामने आई तो सरकार ने बर्खास्तगी जैसे कड़े कदम उठाते हुए जांच का आदेश भी दिया है और जांच के लिए कमेटी भी बनाई है। भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसके लिए सरकार सदन में कानून भी लेकर आएगी। लेकिन इसके साथ ही पायलट ने यह भी कहा कि, यह मुद्दा देश और प्रदेश की धरोहर नौजवानों के भविष्य से जुड़ा है। इनके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। पायलट ने कहा कि, सरकार को इस मामले में कड़े कदम उठाने चाहिए और जांच पारदर्शी होने के साथ ही समयबद्ध तरीके से पूरी होनी चाहिए।

पायलट ने कहा कि, इस मामले में

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

''मोबाइल व बजट''

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 1 फरवरी। मंगलवार को वित्त मंत्री, निर्मला सीतारमण ने अपने स्मार्टफोन से 90 मिनट का बजट भाषण पढ़कर देश का पहला ''पेपरलैस बजट'' प्रस्तुत किया। इस दौरान, स्क्रीन पर टैक्स्ट को पलटने के लिए उन्हें अनेकों बार रुकना पड़ा।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि भाषण के बीच उनके फोन की बैटरी खत्म ना हो जाए, उन्होंने फोन को चार्जर

- वित्त मंत्री ने बजट भाषण के दौरान अपने मोबाइल फोन की खुलकर मदद ली।

से कनैक्ट किया हुआ था। वित्त मंत्री के रुप में यह उनका चौथा बजट था।

तथापि, बजट भाषण के बाद, फाइनैंस बिल पेश करने के लिए उन्हें स्मार्टफोन छोड़कर पेपर से पढ़ना पड़ा, जिसमें उन्होंने टैक्स व शुल्क में बदलावों का विस्तृत विवरण दिया। मीडियम टर्म फिस्क्ल पॉलिसी पर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

निर्मला सीतारमण इकॉनमी को भारत की परम्परागत ''टैन्जिबल करैन्सी'' की दुनिया से उड़ाकर इक्कीसवीं सदी की ''डिजिटल करैन्सी'' के माहौल में ले गयीं

''डिजिटल करैन्सी'' की दुनिया में, जहां विश्व के आधुनिकता देशों, जिनमें अमेरिका भी शामिल है, ने कदम नहीं रखा है, का भारत में आगमन साहसपूर्ण कदम है

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 1 फरवरी। निर्मला सीतारमण ने अपने चौथे बजट में, डिजिटल परिसम्पत्तियों की ट्रेडिंग से होने वाले लाभों पर टैक्स लगाने के अपने प्रस्ताव के जरिये, सीधे तौर पर एक उग्र बहस की शुरूआत कर दी है।

इस प्रस्ताव के साथ ही, वित्त मंत्री ने यह घोषणा भी कर दी कि रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया अपनी स्वयं की ''सैन्ट्रल बैंक डिजिटल करैन्सी'' (सी.बी.डी.सी.) जारी करने पर विचार करेगा।

इन प्रस्तावों और घोषणाओं से, सीतारमण केन्द्रीय बजट को डिजिटल करैन्सी की 21वीं सदी की दुनिया में ले आई हैं।

- हालांकि, इस डिजिटल करैन्सी व्यवस्था के बारे में कई सवाल भी अनुत्तरित हैं।
- चीन, जो इस क्षेत्र में सबसे आगे है, विन्टर ओलम्पिक्स के दौरान चीन की डिजिटल करैन्सी को ओलम्पिक की ऑफिशियल करैन्सी बनाने की पूरी तैयारी में था।
- पर, ओमक्रॉन वायरस व पश्चिमी देशों द्वारा मानव अधिकारों की अवहेलना, विशेषकर वीगर प्रांत की विकट स्थिति के कारण, विन्टर ओलम्पिक में अपनी डिजिटल करैन्सी को गेम्स की ऑफिशियल करैन्सी करने के इरादे से चीन को पीछे हटना पड़ा।
- पर डिजिटल करैन्सी का प्रसार बढ़ रहा है, विशेषकर महंगे आर्ट की खरीद-फरोख्त में।

इससे भारत डिजिटल करैन्सी के के साम्राज्य की अगली पंक्ति में आ गया है, जहां आने का अभी तक केवल कुछ देशों ने ही साहस दिखाया है। इस क्षेत्र का सबसे अग्रणी देश चीन है, जिसने पिछले वर्ष प्रयोग के तौर पर चीनी मुद्रा के रुप में डिजिटल करैन्सी जारी की थी। इन लोगों को चीनी सेन्ट्रल बैंक की अधिकृत डिजिटल करैन्सी का एक डिजिटल वॉलेट दिया गया था, तथा उनसे यह अपेक्षा की गई थी कि वे पैसे के दैनिक लेन-देनों में इसका उपयोग करेंगे।

चीनी कम्यूनिस्ट पार्टी तथा सरकार का विचार था कि वे इस सरकारी चीनी डिजिटल करैन्सी को विधिवत रुप से बीजिंग विन्टर ओलिम्पिक्स के उद्घाटन के समय शुरु करेंगे। चीनियों को उम्मीद थी कि कोई औपचारिक चीनी सी बी डी सी, चीनी युआन को ग्लोबल रिजर्व करैन्सी बना देगी, तथा यह कार्य चीन में अमेरिका से भी पहले हो जायेगा क्योंकि अमेरिका अभी ऐसा कुछ भी करने से बहुत दूर है।

लेकिन, चीन द्वारा वीगर प्रांत में किये गये मानवाधिकारों के हनन को लेकर हुई कूटनीतिक कहा सुनी तथा पश्चिमी देशों द्वारा किये गये ओलम्पिक्स के बहिष्कार के कारण, विन्टर ओलम्पिक्स के उद्घाटन के समय इस करैन्सी की लॉन्चिंग स्थगित कर देनी पड़ी थी।

चीनी इस विचार का मूल्यांकन कर

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

तेजपाल

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 1 फरवरी। सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को तहलका सम्पादक तरुण तेजपाल को आश्वस्त किया कि, बम्बई उच्च न्यायालय की गोवा बैंच के उस फैसले के खिलाफ दायर की गई अपील को सुनवाई के लिये

- दो जजों द्वारा तेजपाल के मामले में सुनवायी करने से माफी मांगने पर, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने तरूण तेजपाल को विश्वास दिलाया कि उनकी सुनवायी शीघ्र करायेंगे, विलम्ब नहीं आने देंगे।

शीघ्र ही सूचीबद्ध किया जायेगा, जिस फैसले में 2013 के यौन-उत्पीड़न केस में ''इन -कैमरा'' सुनवाई के लिये इनकार कर दिया गया था।

यह आश्वासन मुख्य न्यायाधीश

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)